राहुल गांधी का दलित प्रेम

मौसम चुनावी हो अथवा नहीं, कांग्रेस के 'युवराज' राहुल गांधी यदा-कदा ग़रीबों की झोंपड़ियों में चक्कर लगा ही लेते हैं। ग़रीबों - दलितों, आदिवासियों और अछूतों के यहां भोजन करना, अनपढ़ ग्रामीणों से कुछ बातचीत कर लेना और उनकी झोंपड़ी में एकाध रात बिता कर चलते बनना राहुल गांधी द्वारा लोकप्रियता अर्जित करने का एक सस्ता नुस्खा बन गया है। गत लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल ने गांवों का काफ़ी दौरा किया और ग़रीबों की झोंपड़ियों में रातें बिताईं। सोनिया-राहुल के चमचों का कहना है कि राहुल की यह नीति रंग लाई और कांग्रेस को जीत दिलवाने में इसकी सबसे बड़ी भूमिका रही। कांग्रेस की जीत से राहुल गद्‌गद् हो गये। यद्यपि राहुल की ग्राम-यात्राओं का मीडिया में काफ़ी मजाक भी उड़ा, पर बंदा अपनी 'ग़रीबपरवर' छवि बनाने के लिये तत्पर रहा। अभी भी यह उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश के दलितबहुल गांवों में जा कर ग्रामीणों को कृत-कृत्य कर रहा है। जिसके दरवाजे पर वह पहुंच गया और रोटी खा कर सो गया, वह परिवार भी वीवीआईपी हो जाता है। जिससे उसने हाथ मिला लिया, वह महीनों तक हाथ धोता ही नहीं और बार-बार अपने हाथों को निहारता रहेगा। यह स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे यहां नेताओं की छवि देवताओं जैसी बनाई गई है। यही कारण है कि 'सुदर्शन' राहुल को देखने के लिए कस्बों और देहातों के लोग उमड़ पड़ते हैं।

राहुल के किसी न किसी दलित के घर पर रुकने के बाद मीडिया उसकी जबरदस्त कवरेज करता है। राहुल बताते हैं कि दलितों की हालत कितनी खराब है और वे पशुवत जीवन बिता रहे हैं। यह भी कहते हैं कि ग़रीबों के लिये जो योजनायें बनाई जाती हैं और जो पैसा खर्च किया

इसी छवि पर कुर्बान हैं देश के भूखे-नंगे

जाता है, उसका रुपये में मात्र दस पैसा ही उन तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद वे संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ़ बयानबाज़ी करते हैं। वे दलितों, आदिवासियों और अछूतों की बदहाली के लिये संबंधित राज्य के शासकों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं।

सवाल है कि उत्तर प्रदेश के दलितों की बदहाली के लिये क्या मायावती जिम्मेदार हैं या मुलायम सिंह यादव? बिहार की बदहाली के लिये क्या सिर्फ़ लालू जिम्मेदार हैं? इसी तरह दूसरे राज्यों जहां कांग्रेस का नहीं, किसी अन्य पार्टी का शासन है, वहां ग़रीबों की बदहाली के लिये कौन जिम्मेदार है? यह एक प्रमुख सवाल है कि आज जहां राहुल जाकर दलितों के घरों में खाने-पीने और सोने का नाटक रचा रहे हैं, वहां अज़ादी के बाद से साठ वर्षों में पांच-छ: वर्षों को छोड़ दिया जाये तो किस पार्टी का शासन रहा? पूरे भारत में यदि सिर्फ़ दक्षिण को छोड़ दिया जाये तो कांग्रेस का ही शासन रहा है। राहुल गांधी को यह याद रखना चाहिए कि उनके पिता के नाना, उनकी दादी और उनके पिता ही सबसे ज़्यादा लंबे समय तक देश के प्रधानमंत्री रहे। अब भी सत्ता सूत्र का संचालन उनकी मां की चमचा मंडली कर रही है। प्रधानमंत्री बनने के लिये उनकी भी तैयारी चल रही है। क्या राहुल ने कभी यह सोचा है कि दशकों तक देश पर जब उनके परिवार का शासन रहा तो उन्होंने ग़रीबों के उत्थान के लिये क्या किया? उनकी 'ग़रीब परवर' नीतियों से तो अब तक जनता का उद्धार हो जाना चाहिये था। पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? नेहरू ने तो साम्राज्यवादी ताकतों के आगे झुक कर, पूंजीपतियों के आगे सिर नवा कर और उससे भी कुछ नहीं हुआ तो जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा लेकर जनता को 'लूटने-खाने' वालों की एक विशाल व भारीभरकम फ़ौज खड़ी कर दी।

नेहरू के ज़माने में ही मंत्री स्तर पर भ्रष्टाचार और कमीशनबाज़ी शुरू हो गई थी। यह अलग बात थी कि वह भ्रष्टाचार आज जैसा खुला एवं नंगा नहीं था। चवन्नी में ग़रीबों के वोट खरीदने की प्रथा कांग्रेस ने ही शुरू की थी और संभवत: नेहरू भी इस बात से अपरिचित नहीं थे। आज राजनीतिक दुर्दशा का जो आलम है, उसे पैदा करने में कांग्रेस की प्रमुख भूमिका रही है। परिवारवाद, वंशवाद आदि जो बीमारियां हैं, उसे कांग्रेस ने ही पैदा किया और बाद में दूसरे दलों ने इसे अपनाया। चुनावों के दौरान उम्मीदवारों को टिकट बेचना, अपराधियों का सहयोग लेना, जातिवादी समीकरण बनाना, पूंजीपतियों से चंदा लेना और ग्रामीण क्षेत्रों में सामंती तत्वों व अपराधियों को वोट का ठेका दे देना आदि बीमारियां कांग्रेस की ही पैदा की हुई हैं। क्या 'युवराज' राहुल को इन बातों का पता नहीं है।

वर्तमान में जनता की बदहाल दशा के लिये सबसे अधिक कोई जिम्मेवार है तो वह है कांग्रेस। अन्य दल तो बाद में आये और उन्होंने कांग्रेस द्वारा पैदा की गई बुराइयों को अपना लिया।

शुरुआत में लोहिया के नेतृत्व में अपने आपको समाजवादी कहने वाले नेताओं ने कांग्रेस द्वारा फ़ैलाये जाने वाले भ्रष्टाचार का विरोध किया, पर बाद में जैसे ही उनके हाथ में सत्ता आई, वे भी कांग्रेस की राह पर यानी खुल्लमखुल्ला भ्रष्टाचार के मार्ग पर चल पड़े। जार्ज फर्नाडीस और मुलायम सिंह आदि ऐसे ही नेताओं में हैं। इनका किस हद तक पतन हो चुका है, इसे जनता देख रही है। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी पार्टी की आलोचना करते हुये कहा कि भाजपा को कांग्रेसीकरण होता चला जा रहा है, यानी के नेता भी भ्रष्टाचार में डूब चुके हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कांग्रेसी नेताओं एवं आलाकमान ने इस देश की जनता को लूटने-खसोटने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है। जितना अधिक कांग्रेस ने 'खाया-पकाया' है, उसका मुकाबला दूसरी कोई भी पार्टी नहीं कर सकती। इसकी वजह सिर्फ़ एक है और वह है सबसे अधिक समय तक सत्ता कांग्रेस के हाथ में रहना।

आज देखा जाये तो वामपंथी दलों को छोड़ कर किसी भी दल में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। सभी पार्टियां किसी एक व्यक्ति और उसके परिवार वालों की बपौती बन चुकी हैं। राजनीति में अध्यक्ष की जगह सुप्रीमो शब्द प्रचलन में आ गया है। आलाकमान और सुप्रीमो के खिलाफ़ कोई भी नेता अथवा कार्यकर्ता आवाज़ नहीं उठा सकता। अगर उठा दिया तो उसे पार्टी से निकाला जाना चाहे जिस बहाने संभव हो, अवश्यंभावी है। इस तरह हम देखते हैं कि पार्टी पर किसी एक व्यक्ति की तानाशाही और चमचागिरी को कांग्रेस ने ही शुरू किया, बाकी दलों ने तो सिर्फ उसे अपना लिया। इसलिये हमारे राहुल बाबा को पहले अपनी गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिये और तब किसी दूसरे दल अथवा नेता पर छींटाकशी करनी चाहिये। जहां तक राजनीतिक ज्ञान का सवाल है, राहुल को दलितों के गांवों में जाने से पहले एक ट्यूटर रख लेना चाहिये।

□ प्रतिनिधि

बढ़ती महंगाई और बेबस जनता

बढ़ती महंगाई से सभी त्रस्त हैं, विशेषकर ग़रीब लोग। महंगाई ने ग़रीब लोगों की कमर तोड़ दी है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि सरकार तीन महीने में महंगाई पर काबू पा लेगी। अपने आप को देश की मालकिन समझने वाली सोनिया गांधी ने भी कहा था कि 100 दिन में सभी मंत्री अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। सौ के भी दो सौ दिन बीत गये। महंगाई पर सरकार काबू नहीं पा सकी। महंगाई सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती ही चली गई और आम ग़रीबों के साथ-साथ निम्न मध्यम वर्गीय कहे जाने वाले लोग भी त्रस्त हो गये। उनका बजट बिगड़ गया। महंगाई बढ़ी तो रोज़मर्रा इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं की। साथ ही गेहूं, चावल, दाल, तेल, मसाले, सब्जियां आदि वस्तुओं की कीमत इस कदर आसमान छूने लगी कि लोगों की यह समझ में ही नहीं आ रहा कि अपना बजट कैसे संभालें। जाहिर है, जरूरी चीज़ों की कीमत बढ़ने से सभी परेशान हैं।

सवाल है, महंगाई क्यों बढ़ती है? महंगाई तभी बढ़ती है जब मांग की तुलना में आपूर्ति कम हो। तो क्या देश में अनाज का अकाल हो गया है? सब्जियां उगायी नहीं जा रहीं? क्या तेल, मसाले और अन्य खाने-पीने की वस्तुओं का उत्पादन कम हो गया है?

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चुनावी भाषण देते हुए फ़र्माते हैं कि मानसून के कमजोर होने से महंगाई बढ़ी है। अगर मानसून का कमजोर होना महंगाई बढ़ने का कारण होता तो यह आने वाले दिनों में बढ़नी चाहिए थी। पर महंगाई तो तभी से बढ़ रही है जब लोकसभा चुनाव नहीं हुए थे और तत्कालीन कृषि मंत्री शरद पवार ने विदेशों से सड़ा हुआ गेहूं आयात करवाया था। दालों की कीमत आसमान छूने पर दालों का भी आयात किया गया। फ़िर भी महंगाई घटी नहीं। ज्यों की त्यों बनी रही। फ़िर लोकसभा चुनाव के बाद मनमोहन सिंह दुबारा प्रधानमंत्री बने। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान ये लोग चिल्ला रहे थे कि उनकी सरकार बनते ही महंगाई पर काबू पा लिया जायेगा। लेकिन ये सारी घोषणायें थोथी साबित हुईं। अब मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि जमाखोरों और काला बाज़ारियों के खिलाफ़ सरकार कदम उठायेगी। यानी सरकार का मानना है कि जमाखोरी और कालाबाज़ारी महंगाई बढ़ने के कारण हैं। अगर ऐसा है तो सरकार को इनके खिलाफ़ कार्रवाई करने से कौन रोक रहा है? अगर सरकार जमाखोरों, कालाबाज़ारियों व फ्यूचर ट्रेडिंग करने वालों के खिलाफ़ कड़े कदम उठाये, हर वस्तुओं की अधिकतम कीमत तय कर दे तो जनता को बड़ी राहत मिलेगी। पर विडंबना तो यही है कि सरकार ऐसा कर नहीं सकती। सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती है? जमाखोरी, काला बाज़ारी के खिलाफ़ कड़े कानून बने हुए हैं और उन्हें देश भर में लागू करवाने के लिए पर्याप्त अमला मौजूद है। फ़िर समस्या क्या है?

देखने भर को रह गयीं सब्जियां

समस्या यह है कि सरकार अगर जमाखोरों, कालाबाज़ारियों और सट्टेबाजों के खिलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दे तो स्वयं ही भरभरा कर गिरने का खतरा उसके सामने पैदा हो जाये। वर्तमान सरकार जनता के समर्थन से कम और इनके समर्थन और सहयोग से ज़्यादा चल रही है। फ़िर सरकार अपने सहयोगियों के खिलाफ़ कार्रवाई कैसे कर सकती है? मनमोहन सिंह और उनकी मालकिन सोनिया को उन लोगों का दर्द महसूस नहीं हो सकता जो महंगाई की वजह से आधा पेट खा कर ही समय गुजारने को मजबूर हैं। उन्हें उन किसानों का दर्द महसूस नहीं हो सकता जो कड़ी मेहनत कर फ़सल उगाते हैं, फ़िर भी भूखे रहने पर मजबूर होते हैं और कर्ज के जाल में फंस कर उससे मुक्ति पाने के लिए दुनिया को ही अलविदा कह देते हैं। विडंबना यह भी है कि अनाज की बढ़ी हुई कीमतों से किसानों को कोई फ़ायदा नहीं होता। इससे फ़ायदा होता है उन सट्टेबाजों और जमाखोरों को जो फ़सल तैयार होने पर उसकी खरीद करने के लिए भाव गिरा देते हैं। कभी-कभी तो भाव इतना गिरा दिया जाता है कि किसानों को फ़सल उगाने का लागत मूल्य भी नहीं मिल पाता। खेती में होने वाले इस घाटे के कारण बहुतेरे किसान अब खेती-किसानी छोड़ औद्योगिक शहरों में मज़दूरी करना ज्यादा पसंद करने लगे हैं। यही नहीं, सरकार भी किसानों की ऊपज का उचित मूल्य नहीं देकर सट्टेबाजों को बढ़ावा देती है। सरकारी खरीद केंद्रों पर किसान अनाज बेचने के लिए धक्के खाते हैं। किसान अपना खून-पसीना बहा कर सोने जैसी जो फ़सल उगाते हैं, उसे निजी कंपनियां कौड़ियों के मोल खरीद लेती हैं और फ़िर उसे या उससे बने उत्पादों को बेच कर भरपूर मुनाफ़ा कमाती हैं। क्या मनमोहन सिंह की सरकार इसे रोक पाने में सक्षम है? कतई नहीं। मनमोहन सिंह क्या, वर्तमान व्यवस्था में वामपंथी दलों की सरकार भी इस पर काबू नहीं पा सकती। उदाहरण के रूप में हमारे सामने पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा मौजूद हैं।

आज जिस चीज़ की कृत्रिम कमी बतायी जाती है, मौसम और मानसून का ठीकरा फोड़ा जाता है, कल इसी बहाने के आधार पर उसी के आयात की जरूरत बतायी जायेगी। फ़िर आयात के इस खेल में घटिया चीज़ें मंगवाई जायेंगी और सरकार के मंत्री दलाली खायेंगे। कीमतें फ़िर भी नहीं घटेंगी। वैसे भी, अनुभव के आधार पर जनता यह जानती है कि एक बार जिस चीज़ की कीमत बढ़ गई, वह कम होने के बजाय और भी बढ़ती ही चली जायेगी।

□ प्रतिनिधि